

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PARTI—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 2004/वैशाख 22, 1926

No. 106]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 12, 2004/VAISAKHA 22, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2004

सं. 63 (आर ई-2003)/2002—2007

विषय: टैरिफ रेट कोटा के तहत विभिन्न मदों के आयात हेतु प्रक्रिया।

फा. सं. 01/89/180/0001/एएम 04/पीसी-1ए.—निर्यात-आयात नीति, 2002—2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

पैरा 2.60 टैरिफ रेट कोटा स्कीम के तहत आयात हेतु प्रक्रिया।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2002 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार चार मदों यानी (1) स्किम्ड और सम्पूर्ण दूघ पावडर, शिशुओं हेतु दूध खाद्य (0402.10 अथवा 0402.21) (2) मक्का अन्य (1005.90) (3) कच्चे सूरजमुखी बीज अथवा कुसुंभ का तेल अथवा उसके हिस्से (1512.11) और (4) रिफाइंड तोरिया, कोल्जा अथवा सरसों का तेल, अन्य (15.14.19 अथवा 1514.99) की निम्नानुसार रियायती दरों पर सीमाशुल्क के साथ-साथ मात्राओं की एक वित्तीय वर्ष में आयात की अनुमति दी जाती है:-

क्रमांक	आईटीसी कोड नं. और मद	कोटे की मात्रा	रियायती शुल्क
1.	टैरिफ कोड नं. 0402.10 अथवा 0402.21 रिकम्ड और सम्पूर्ण दूध पावडर। शिशुओं आदि हेतु खाद्य दूध		
2.	टैरिफ कोड नं. 15!2.11 मक्का अन्य (1005.90)	5,00,000 मी.टन	15 %
3.	टैरिफ कोड नं. 1512.11 कच्चा सूरजमुखी बीज अथवा कुसुम तेज अथवा उसके हिस्से।	150,000 ਸੀ.ਟਜ	50 %
4.	टैरिफ कोड नं. 1514.19 और 1514.99 तोरिया, कोल्जा अथवा सरसों का तेल अन्य रिफाइंड	150,000 ਸੀ. ਟਜ	45 %

- 2. कोटा के आबंटन के लिए पात्रः
- (क) मिल्क पावडर (टैरिफ कोड सं. 040210 या 0402.21): एन डी डी बी, एस टी सी, एन सी डी एफ नैफेड, एमएमटीसी, पीईसी, एन टी सी एल कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं।
- (ख) मक्का (कार्न) टैरिफ कोड सं. : 15.90): नैफेड, एसटीसी, एमएमटीसी, पीईसी, एस टीसीएल और राज्य सहकारी विपणन व कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं।
- (ग) <u>कच्चा सूरजमुखी बीज र कसंभ तेल अथवा उसके हिस्से (टैरिफ कोड सं. 1512.11) :</u> एन डी डी बी, एसटीसी, नेफे एस टी सी एल ओर सी डब्ल्यू सी, राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी नागिर आपूर्ति निगम कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं।
- (घ) रिफाइन्ड रूया, कोल्जा या सरसों तेल, अन्य (टैरिफ कोड सं. 1514.19 या 1514.99): गुरुवित, एसटीसी, नेफेड, एसटीसीएल, सी डब्ल्यू सी, राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य र

सभी गात्र आवेदक प्राप्त आवेदनों के अनुसार कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं।

- 3 जः यथा उल्लिखित कोटे का उपयोग करने के सभी इच्छुक पात्र प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-1100 में निर्यात-आयात सुविधा समिति को आवेदन कर सकते हैं। अपेक्षित/निर्धारित दस्तावेजों सिट्ट पूर्ण आवेदन-पत्र इस कार्यालय को प्रत्येक वितीय वर्ष की 30 जून को या इससे पहले पहुंच ज चाहिए।
- .. आयात वित्तीय वर्ष 31 मार्च से पहले पूरे कर लिए जाने चाहिए अर्थात सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कंसाइन्मेंट इस.तारीख से पहले क्लीयर कर दिए जाने चाहिए।
- 5. चूंकि मक्के का आयात राज्य व्यापार शासन के अधीन हैं, अतः कोटे के आवंटी अर्थात इस मद के लिए ऊपर पैरा 1(ख) में नामजद अभिकरणों को निर्यात-आयात नीति, 2002-2007 के पेरा 2.11 के अनुसार सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 1-3-2002 की क्रम सं. 21 (ख) पर यथानिर्दिष्ट आवंटित मात्राओं के लिए आयात लाइसेंस भी दिया जायेगा यदि वे भारतीय खाद्य निगम के जरिये आयात नहीं करना चाहते हैं।
- 6. इन आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड-1, 2002-2007 के परिशिष्ट-29 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- 7. आवेदकों को कोटे का आवंटन विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात-आयात सुविधा समिति द्वारा दिया जायेगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th May, 2004

No. 63 (RE-2003)/2002---2007

Subject: Procedure for import of various items under Tariff Rate Quota (TRQ).

F. No. 01/89/180/0001/AM 04/PC-1A.— In exercise of powers conferred under Para 2.4 of Export and Import Policy, 2002—2007, the DGFT makes the following amendments in the Handbook of Procedures, Vol I:—

Para 2.60 Procedure for import Under the Tariff Rate Quota Scheme

Attention is invited to Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), notification no. 21/2002-Customs dated 1st March, 2002. As per the notification, import of four items viz., (1) Skimmed and whole milk powder, milk food for babies etc. (0402.10 or 0402.21) (2) Maize (corn), other (1005.90) (3) Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (1512.11) and (4) Refined rape, colza or mustard oil, other (1514.19 or 1514.99) is allowed in a financial year, up to the quantities as well as such concessional rates of customs duty as indicated below:

S.No.	ITC Code No. & Item	Quantity of	Concessional
1.	Tariff Code No. 0402.10 or 0402.21 Skimmed and whole Milk	Quota 150,000 MTs	duty 15%
2.	Powder. Milk Food for babies etc.		
	Tariff Code No. 1512.11 Maize (Corn) other (1005.90)	5,00,000 MTs	15%
3.	Tariff Code No. 1512.11 Crude Sunflower seed or safflower oil or fractions thereof	150,000 MTs	50%
4.	Tariff Code No. 1514.19 & 1514.99 Rape, Colza or Mustard Oil, Other (Refined)	150,000 MTs	45%

2. Eligible entities for allocation of quota:

- (a) Milk Powder (Tariff Code No. 0402.10 or 0402.21):
 National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation(STC), National Cooperative Dairy Federation (NCDF), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED), Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC), Projects & Equipment Corporation of India Limited(PEC) and Spices Trading Corporation Limited (STCL) are eligible to avail the quota.
- (b) Maize(corn)(Tariff Code No. .1005.90): National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED), State Trading Corporation (STC), Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC), Projects & Equipment Corporation of India Limited(PEC), Spices Trading Corporation Limited (STCL) and State Cooperative Marketing Federations are eligible to avail the quota.
- Crude sunflower seed or safflower oil or fractions (c) thereof(Tariff Code No. 1512.11): National Dairy Development Board(NDDB), State Trading Corporation National Agricultural Cooperative Marketing (STC), Federation of India Ltd.(NAFED) Spices Trading Corporation Limited (STCL) and Central Warehousing Corporation (CWC) State Cooperative Marketing Federation & State Cooperative Civil Supplies Corporation are eligible to avail the quota.
- (d) Refined rape, colza or mustard oil, other(Tariff Code No. 1514.19 or 1514.99): National Dairy Development Board(NDDB), State Trading Corporation (STC), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED), Spices Trading Corporation Limited (STCL) and Central Warehousing Corporation (CWC) State Cooperative Marketing Federation & State Cooperative Civil Supplies Corporation are eligible to avail the quota.

All the eligible entities are eligible to avail the quotas as per the request of the applicants received.

- 3. All eligible entities desiring availment of the quota as mentioned above, may make application to Exim Facilitation Committee (EFC) in the form given in Appendix 8 of the Handbook of Procedures in the office of Directorate General of Foreign Trade(DGFT), Udyog Bhawan, New Delhi-110 011. The completed application forms along with the required/prescribed documents must reach this office on or before 30th June of each financial year.
- 4. The imports have to be completed before 31st March of the financial year i.e. the consignments must be cleared by the customs authorities before this date.
- 5. Since import of maize (corn) is under State Trading Regime (STR), the allottes of quota i.e. designated agencies in para 1 (b) above for this item shall also be granted an import licence for the allotted quantities as indicated at Sl. No. 21(b) of Customs Notification No. 21/2002 dated 1.3.2002 in terms of para 2.11 of Exim Policy, 2002-2007, if they do not wish to make the imports through Food Corporation of India (FCI).
- 6. The application fee for these applications shall be paid according to the procedure contained in appendix 29 to Handbook of Procedures, Vol.I, 2002-2007.
- 7. The allocation of quota, among the applicants shall be made by the Exim Facilitation Committee (EFC) in the DGFT.

This issues in the Public interest.

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade